

अवैध तरीके से संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को किस कानून के तहत बेदखल किया जाता है जानिए-

मान लीजिए कि श्री ए के पास एक घर है, जिसे श्री ब ने गलत तरीके से कब्जे में ले लिया है। श्री ए अदालत में जाते हैं और श्री ब के खिलाफ मामला दर्ज करते हैं। अदालत श्री ब को घर खाली करने का आदेश देती है, लेकिन श्री ब आदेश का पालन नहीं करते हैं तब यह प्रक्रिया किस कानून के अंतर्गत होगी जानिए -

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 94 के प्रावधान के अनुसार-



युवा प्रदेश समाचार पत्र
- लेखक बीआर
अहिरवार (एडवोकेट एवं
विधिक सलाहकार
होशंगाबाद) 9827737665

नियम 94- किसी भी मामले में जहां कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को गलत तरीके से कब्जे में ले रहा है, और वह संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की है, तो अदालत उस व्यक्ति को संपत्ति को खाली करने का आदेश दे सकती है, और संपत्ति को सही मालिक को सौंप सकती है।

इस नियम के तहत, अदालत यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को गलत तरीके से कब्जे में न ले, और संपत्ति को सही मालिक को सौंपा जाए।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 95 के प्रावधान के अनुसार- नियम 95- यदि कोई व्यक्ति आदेश 21 नियम 94 के तहत दिए गए आदेश का पालन नहीं करता है, तो अदालत उस व्यक्ति को जुर्माना लगा सकती है, या उसे कारावास में भेज सकती है, या दोनों ही कर सकती है।

इस नियम के तहत, अदालत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है जो आदेश 21 नियम 94 के तहत दिए गए आदेश का पालन नहीं करते हैं, और सुनिश्चित करती है कि अदालत के आदेशों का पालन किया जाए।

BNS-296 सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने गाना कब अपराध होता है जानिए-

बहुत से मनचले ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता वाले गाने गाते हैं या जोर जोर से अश्लील गाली देते हैं जिससे आम व्यक्ति को अशोभनीय लगता है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानून क्या कार्यवाही करेगा जानिए-

भारतीय न्याय संहिता,

2023 की धारा 296 की परिभाषा??

अगर कोई व्यक्ति अश्लील कार्य और गाने निम्नलिखित परिस्थितियों में करता है -

1. किसी लोक स्थान पर- यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि सड़क, पार्क, बाजार, या अन्य स्थान जहाँ लोगों का आना-जाना होता है, अश्लील कार्य करता है या अश्लील गाना गाता है, तो वह अपराध है।
2. किसी पवाड़े पर - यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक आयोजन, जैसे कि उत्सव, मेला, या अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में, अश्लील कार्य करता है या अश्लील गाना गाता है, तो वह अपराध है।

इन परिस्थितियों में, अश्लील कार्य या गाने से तात्पर्य है कि ऐसा कार्य या गाना जो अश्लील, अभद्र, या अनुचित है, और जो लोगों को परेशान या अपमानित कर सकता है। तब यह अपराध होगा।

THE BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023, SECTION 296 PROVISION OF PUNISHMENT

इस धारा के अपराध संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं अर्थात पुलिस थाने में इस अपराध की एफआईआर दर्ज होगी एवं उचित कार्यवाही कर आरोपी को जमानत पर छोड़ सकती है। इस अपराध की सुनवाई कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है एवं यह समझोते योग्य नहीं है अर्थात राजीनामा नहीं किया जा सकता है।

सजा- इस धारा के अपराध के लिए तीन माह की कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

● **लेखक बीआर अहिरवार (पत्रकार एवं विधिक सलाहकार होशंगाबाद)**

क्रांतिसूर्य टंट्या मामा भारत के जनजातीय गौरव पुरुष थे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री टंट्या मामा के बलिदान दिवस समारोह में वर्चुअली शामिल हुए



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि क्रांतिसूर्य टंट्या मामा भील समाज के ही नहीं, भारत के जनजातीय गौरव पुरुष थे। टंट्या मामा को मैं शत-शत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जीवन भर अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर शोषितों की आवाज बनकर स्वतंत्रता की अलख जगाई। उनकी पुण्य-तिथि के अवसर पर टंट्या भील विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बलिदान दिवस पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आजादी के बाद कई दशकों तक देश के तत्कालीन सत्ताधीशों ने जनजातीय जननायकों को यथोचित मान-सम्मान नहीं दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बुधवार को मंत्रालय से टंट्या मामा की पुण्यतिथि के अवसर पर क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय



खरगोन में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ, जिनके आने के बाद स्थिति बदली है और उनके नेतृत्व में हमने फिर चाहे टंट्या मामा हो या भगवान बिरसा मुंडा जैसे जननायकों के कामों को आज के युवा के मानस पटल पर पुनर्जीवित किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि खरगोन में भील विश्वविद्यालय का नाम टंट्या मामा के नाम पर रखना भी उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तातिा भील का टंट्या नाम अंग्रेजों

द्वारा दिया गया था। जिसे बाद में लोगों द्वारा प्यार से टंट्या मामा कहकर पुकारने लगे। टंट्या गुरिल्ला युद्ध कौशल में माहिर थे कि सशक्त शक्तिशाली, सब प्रकार से सम्पन्न अंग्रेजी हुकुमत की नाक में उन्होंने दम किया हुआ था। वे अपने समाज में रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। वे अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बाँटा करते थे। उनकी सोच थी कि हिन्दुस्तान का पैसा हिन्दुस्तान के लोगों के काम आए, न कि उसे अंग्रेज लूट कर ले जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने जनजातीय समाज के जननायकों की गौरव गाथा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य टंट्या मामा के जन्म स्थल क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्चतम शिक्षा प्रदान करना था।

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल

पाठ्यक्रम भी किए जाएं शुरू

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यहां पैरामेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रमों को भी प्रारंभ किया जाएगा। विश्वविद्यालय को प्रारंभ हुए एक वर्ष भी पूर्ण नहीं हुआ है। दिनांक 9 फरवरी 2024 को स्वीकृति के बाद सिर्फ शिक्षा ही नहीं रोजगार के अवसर भी इस विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ सामने आए। इसमें 140 शैक्षणिक, 14 प्रशासकीय और 81 गैर शैक्षिकीय इस प्रकार कुल 235 पद स्वीकृत किए गए हैं।

संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में चार नए पाठ्यक्रम होंगे प्रारंभ

भोपाल। भोपाल में स्थित संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क (तस्क्) में चार नए अत्याधुनिक पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल के मार्गदर्शन में इस परियोजना को नई दिशा दी जा रही है। इन पाठ्यक्रमों में साइबर एंड नेटवर्क सिक्युरिटी एनीमेशन - मोशन ग्राफिक, गेमिंग टेक्नोलॉजी और एआर एंड वीआर शामिल हैं। इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों से लिया जाएगा। उपरोक्त कोर्सेज के संचालन के लिए कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं एमएसएमई मंत्री श्री चेतन काश्यप की उपस्थिति में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तकनीकी साझेदारी के लिए आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गांधीनगर को नॉलेज पार्टनर के रूप में चुना गया है।



मध्यप्रदेश पर्यटन को मिला 'सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य' का सम्मान अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने तवांग में ATOAI के सम्मेलन में सौंपा सम्मान

भोपाल। मध्यप्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने के लिये मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रयासों को निरंतर सफलता हासिल हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ATOAI) के राष्ट्रीय सम्मेलन में म.प्र. टूरिज्म बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य (बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म स्टेट) के रूप में सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने टूरिज्म बोर्ड के संयुक्त संचालक डॉ. एस.के. श्रीवास्तव को यह सम्मान सौंपा। सर्वश्रेष्ठ साहसिक राज्य पुरस्कार उन राज्यों को दिया जाता है, जिन्होंने बुनियादी ढांचे, विविध गतिविधियों एवं



नवाचारों के माध्यम से साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता हासिल की हो। प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति विभाग एवं प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने पुरस्कार पर हर्ष व्यक्त

करते हुए कहा कि संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी के मार्गदर्शन में प्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं। यह पुरस्कार न केवल हमारे प्रदेश की अद्वितीय प्राकृतिक संपदा और विविध पर्यटन अनुभवों की पहचान है, बल्कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का भी परिणाम है। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा, पचमढ़ी, अमरकंटक और नर्मदा घाटी जैसे स्थानों ने साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कबाड़ी बड़े जैन को अनुपपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार



अनूप कुमार गुप्ता

ब्यूरो चीफ अनुपपुर

अनुपपुर/ कोतमा। थाना कोतमा पुलिस द्वारा कबाड़ चोरी के दो मामलों में फरार आरोपी सुमित उर्फ बड़े जैन को किया गिरफ्तार,,,,,दिनांक 19/09/2024 को मूखबिर द्वारा सूचना पर एक 409 चार पहिया वाहन में चोरी के लोहे के कबाड़ लोड होकर परिवहन की सूचना पर मौके से रेड कार्रवाई की गई थी ,मौके पर 409 वाहन क्रमांक एमपी- 18-ब्र-24 33 मौके से मिली वाहन में चोरी के लोहे का कबाड़ भरा पाया गया जिसके संबंध में चालक रवि सिंह पिता ओंकार सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी जरवाही थाना बुढार जिला शहडोल, से पूछताछ करने पर कि लोहे कबाड़ के बबलू जायसवाल निवासी मनमारी कोतमा के पास से लोड कराकर सुमित जैन उर्फ बड़े जैन निवासी बुढार के पास लेकर जाना बताया था वाहन में लोड 04 टन माल कीमत एक लाख रुपए एवं वाहन की कीमत 5 लाख रुपए कुल 6 लाख रुपए का जप्त कर आरोपी चालक रवि सिंह,बबलू उर्फ मुकेश जायसवाल एवं सुमित उर्फ बड़े जैन के खिलाफ अपराध क्रमांक 400/24 धारा 303(2), 317(5), 61(2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया,आरोपी रवि सिंह पिता ओंकार सिंह एवं बबलू उर्फ मुकेश जायसवाल पिता श्रीमन जयसवाल निवासी मनमारी कोतमा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था, मामले में आरोपी सुमित जैन उर्फ बड़े जैन फरार था। दिनांक 06.11.2044 को पुनः वाहन पीकप क्रमांक रजि.65ब्र-0757 में अवैध कबाड़ 2 टन कुल कीमत 350000 रुपए का पाए जाने पर चालक संत कुमार यादव पिता राम कृपाल यादव निवासी ग्राम शीथली थाना बुढार एवं पप्पू ताम्रकार निवासी कोतमा, एवं सुमित जैन उर्फ बर्थडे जैन निवासी बुढार के खिलाफ अपराध क्रमांक 433/ 24 धारा 303(2), 317(5) 61 (2) 3 /5 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, उक्त मामले में चालक संतकुमार एवं पप्पू ताम्रकार पूर्व में गिरफ्तार हो चुका था मामले में सुमित जैन उर्फ बड़े जैन फरार था उक्त दोनों मामलों में आज दिनांक 26.11.2024 को आरोपी सुमित जैन उर्फ बड़े जैन पिता स्वर्गीय प्रेम जैन निवासी बुढार को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है इसके खिलाफ कोतमा,चचाई,धनपुरी,बुढार में कई मामले और भी पंजीबद्ध हैं उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतमा सुंदरेश सिंह, प्रधान आरक्षक 108 रामखेलावन यादव, प्रधान आरक्षक 52 दिनेश राठौर, आरक्षक 224 चक्रधर तिवारी, आरक्षक 575 दिनेश किराडे, एवं सायबर सेल प्र.आर.राजेन्द्र ,आर. पंकज मिश्रा की मुख्य भूमिका रही है।

स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला सक्रिय रूप से योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अभियान का करें बेहतर क्रियान्वयन-कलेक्टर

गंभीर बीमारी के चिन्हित मरीजों का निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाए उपचार-कलेक्टर

अनूप कुमार गुप्ता ब्यूरो चीफ अनुपपुर
अनुपपुर। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला संवेदनशीलता एवं गंभीरता के आधार पर शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अभियान का बेहतर क्रियान्वयन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिले की सभी एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता एक्टिव होकर कार्य करें। गंभीर बीमारी के चिन्हित मरीजों की जांच एवं उपचार शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार समय में करना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा किए जा रहे कार्यों की गंभीरता से मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर बैठकें आयोजित कर कार्यों की समीक्षा खंड चिकित्सा अधिकारी करें। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए.के. अवधिया, सिविल सर्जन तथा जिले के सभी खंड चिकित्सा अधिकारी सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला उपस्थित था। बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला एवं खंड चिकित्सालय में बेहतर साफ सफाई व्यवस्था हो तथा चिकित्सालय आकर्षित तरीके से दिखाई दे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थित तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन करें तथा मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। बैठक में कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय के एएनसी वार्ड में गर्भवती माताओं के पंजीयन, संस्थागत प्रसव तथा होम डिलीवरी की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान कलेक्टर ने परिवार



कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत नसबंदी तथा राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए ऑपरेशन के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने बच्चों के टीकाकरण की जनपदवार जानकारी प्राप्त की तथा टीकाकरण कर शासन के निर्धारित मापदंडों के अनुसार गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया एवं डेंगू, जिले में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चिन्हित मरीज एवं ऐसे मरीज जो स्वयं विधिवत रूप से उपचार नहीं करा रहे हैं, ऐसे मरीजों की सूची संधारित कर उनका इलाज करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिले में सिकल सेल एनीमिया से हुए मृत्यु के संबंध में भी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। बैठक में कलेक्टर ने खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में

सिकल सेल एनीमिया की जांच प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके लिए सुपरवाइजर, एएनएम तथा आशा कार्यकर्ता मैदानी स्तर पर एक्टिव होकर कार्य करें। उन्होंने आयुष्मान कार्ड के प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे उपचार एवं लक्ष्य की जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि क्षय रोग के चिन्हित मरीजों की स्थिति एवं दवाई वितरण समय पर हो तथा गंभीर बीमारी के मरीजों के घर जाकर उन्हें दवा प्रदान किया जाए तथा इसकी मॉनीटरिंग भी की जाए। बैठक में कलेक्टर ने जननी सुरक्षा योजना, सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती किए गए बच्चों की जानकारी सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

विशेष जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब

अनूप गुप्ता ब्यूरो चीफ अनुपपुर

अनुपपुर। मध्यप्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल द्वारा विशेष जागरूकता अभियान -हम होंगे कामयाब- पखवाड़ा दिनांक 25.11.2024 से 10.12.2024 तक चलाया जा रहा है, आज दिनांक 28.11.2024 को सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुपपुर की करीब 60 बालिकाएं, विद्यालय के शिक्षको के साथ महिला थाना अनुपपुर, पुलिस थाना की कार्यप्रणाली देखने एवं जानने स्वयं की जिज्ञासा से उपस्थित आयी, शिक्षको की उपस्थिति मे सभी बालिकाओ को सम्मान सहित बैठाया जाकर -हम होंगे कामयाब- जागरूकता अभियान के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं इन कानूनों के उल्लंघन,महिलाओ के अधिकारो, हेल्पलाइन SHE BOX PORTAL, हैजटैग पाक्सो, घरेलू हिंसा अधिनियम- के बारे मे जानकारी दी जाकर जागरूक किया गया, बालिकाओ को

थाना की कार्यप्रणाली बतायी एवं दिखाई जाकर जानकारी दी गई, बालिकाओ द्वारा जिज्ञासा से पूछे गये प्रश्नो का समाधान कारक जबाब दिया गया । हम होंगे कामयाब अभियान के दौरान आज दिनांक 28.11.2024 को हॉटस्पॉट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुपपुर मे जाकर शिक्षको की उपस्थिति मे बाल विवाह मुक्त भारत तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम एवं इन कानूनों के उल्लंघन, महिलाओ के अधिकारो, हेल्पलाइन SHE BOX PORTAL, हैजटैग पाक्सो, घरेलू हिंसा अधिनियम विषय पर चर्चा कर छात्राओ एवं विद्यालय स्टाफ को विस्तृत जानकारी दी जाकर जागरूक किया गया । जागरूकता अभियान मे शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनुपपुर में करीब 250 छात्राएं एवं विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे है, छात्राओ को बिना भय,संकोच निडर होकर कानून की मदद लेने हेतु समझाया गया । महिला थाना अनुपपुर स्टाफ उपनिरी. वीरेन्द्र तिवारी, आर. कपिल देव चक्रवर्ती, म.आर. प्रवीन गौतम द्वारा जागरूकता अभियान की विस्तृत जानकारी छात्राओ को दी गई।

सेहरा जंगल में दिखे 18 हाथी, आधा दर्जन से अधिक गांव की बिजली कटवाई, ड्रोन से निगरानी

रिपोर्ट = राजू राय

शहडोल जिले के ब्यूँहारी वन परिक्षेत्र में लगभग 20 जंगली हाथी एक महीने से विचरण कर रहे हैं। हाथियों ने अब तक कई किसानों की दर्जनों एकड़ फसल को तबाह कर दिया है। खलिहानों में रखे अनाज को भी हाथी खा गए हैं। ग्रामीणों की सुरक्षा के साथ-साथ जंगली हाथियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। बीते दिनों शहडोल और सतना की सीमा पर एक जंगली हाथी की करंट लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वन विभाग और अधिक सतर्क हो गया है। जंगली

हाथियों के मूवमेंट वाले क्षेत्रों में पहले से ही बिजली बंद करवाई जा रही है। हाथियों की निगरानी के लिए विभाग अब ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहा है। बताया गया कि ब्यूँहारी वन परिक्षेत्र के सेहरा जंगल में जंगली हाथियों की लोकेशन मंगलवार सुबह मिली है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक बीती रात हाथी घने जंगल के भीतर चले गए थे, लेकिन ड्रोन कैमरे की मदद से उनकी लोकेशन का पता चला। ड्रोन में 18 हाथी दिखाई दिए, जो बुढ़वा क्षेत्र के सेहरा जंगल में विचरण कर रहे हैं। आसपास के गांवों में वन विभाग की टीम ने मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। ड्रोन कैमरे से हाथियों का मूवमेंट देखकर बिजली की आपूर्ति कटवाई जा

रही है। एसडीओ फॉरेस्ट रेशम सिंह धुवें ने बताया कि रामपुरवा, बुढ़वा, मऊ सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों में बिजली बंद करवा दी गई है। हाथियों के मूवमेंट वाले क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है, ताकि करंट लगने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। ग्रामीणों ने बताया कि हाथियों के मूवमेंट से वे काफी परेशान हैं। खेतों में लगी फसल को हाथी नष्ट कर रहे हैं, खलिहानों में रखा अनाज भी खा रहे हैं। अब रात में भी अंधेरे में रहना पड़ रहा है। हालांकि, वन विभाग हाथियों को करंट से बचाने और किसी घटना को रोकने के लिए सही कदम उठा रहा है, लेकिन इस स्थिति से ग्रामीणों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमझोर में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन

केलाश कुमार - वरिष्ठ पत्रकार

शहडोल/अमझोर - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमझोर में रक्तदान महानदान परोपकार सर्वो धर्म: के तत्वाधान में सोमवार 02 दिसंबर 2024 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉ ईश्वर प्रसाद लोधी एवं इनायत उल्ला खान तथा समस्त स्टाफ रक्त मित्र अनुराग यादव और सौरभ गौतम के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें शहडोल ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं से रक्त लिया गया एवं निशुल्क जांच की गई रक्तदान में कुल मिलाकर 20 रक्त मित्रों ने रक्त दान किया जिसमें प्रमुख रूप पुष्पा तिवारी रावेंद्र शुक्ला,मनीष मिश्रा, सौरभ गुप्ता,भारत लाल प्रजापति, गोरेलाल यादव,अनुज यादव गणेश सिंह,धर्मेन्द्र सिंह,रामजस दीमर,राजकुमार मौर्य,अजय जोगी,अजीत सेन,रवेंद्र सिंह, संजय कुमार साहू,देवांश तिवारी, फूलचंद अहिरवार,राजेश अहिरवार,विवेक गुप्ता,मोहम्मद अयाज खान सहित उन लोगों ने रक्तदान का निशुल्क जांच कराया इस रूप के माध्यम से अब तक कुल मिलाकर 52 लोगों को रक्तदान का सेवा प्रदान की गई है अनुराग यादव जो इस रूप के सदस्य उन्होंने कहा कि हमारे उद्देश्य लोगों को शिविर के माध्यम से रक्तदान के लिए प्रेरित करना एवं उसके लाभ को बताना है हमारे रूप में जिले की युवा जुड़कर रक्तदान कर लोगों को जीवन बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं और जीवन बचा सकते हैं।



आवश्यकता है

मैरीकलस मशरूम सुपरफूड्स प्रा0 लि0
स्थान बलौद मे , कार्य हेतु लड़के एवं लड़कियों
की आवश्यकता है (मासिक वेतन 7000/-)
रहना एवं खाना फ्री रहेगा ,इच्छुक व्यक्ति आज
ही संपर्क करे - 9425709472

हीटवेव की स्थिति वाले 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान को संयुक्त रूप से लागू किया गया है देश में हीटवेव की खतरनाक दर

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक स्तर पर वार्षिक तापमान में वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में हीटवेव की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता में दृष्टिगोचर होती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में भी यह परिलक्षित होती है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, सामान्य तौर पर, उत्तरी मैदानी इलाकों और मध्य भारत को कवर करने वाले हीट कोर जोन में हीटवेव की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। हाल ही में आईएमडी ने हीटवेव पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया जो भारत में हीटवेव पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में हीटवेव के कारणों में कमी लाने के लिए राज्यों की मदद से अनेक पहलें की गई हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना इन प्रमुख पहलों में शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत विकास के लिए निम्न-



कार्बन वाली रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है। आईएमडी, देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के समन्वय के साथ, निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार लाने की दिशा में कई कदम उठा रहा है, जिससे हीटवेव सहित चरम मौसम के दौरान जीवन और संपत्ति के नुकसान में

कमी लाने में मदद मिली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से हीटवेव की स्थिति वाले 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान को संयुक्त रूप से लागू किया गया है। हीटवेव के कारण पिछले वर्ष फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सब्जियों ने खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव डाला।

पुलिस महानिदेशक के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई परेड का आयोजन दी गई भावभीनी विदाई

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश

पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना के सेवानिवृत्ति के अवसर पर विदाई परेड का आयोजन मोतीलाल नेहरू पुलिस स्टेडियम भोपाल में किया गया। परेड से पहले पुलिस महानिदेशक ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। विदाई परेड में परेड कमाण्डर की जिम्मेदारी भापुसे सोनाक्षी सक्सेना डीसीपी इंटेलिजेंस भोपाल तथा परेड टूआईसी सहायक सेनानी के नेतृत्व में आठ पोलिटून तथा पुलिस बैण्ड दल द्वारा परेड की गई। पुलिस महानिदेशक द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया

उसके बाद आकर्षक मार्च पास्ट हुआ। सेवानिवृत्ति के अवसर पर अपने संबोधन में सुधीर सक्सेना ने कहा कि एक अत्यंत भव्य परेड का आज आपने प्रदर्शन किया है। इसके लिये मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके इस प्रदर्शन के लिए मैं एडीजी एसएफ तथा उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं समर्पण के फलस्वरूप आपके उच्च कोटि के प्रदर्शन के हम सभी साक्षी बने हैं। मध्य प्रदेश पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा इन शहीदों



के आत्मदान की नींव पर ही मध्य प्रदेश पुलिस की गौरवशाली इमारत खड़ी हुई है। समस्त शहीदों और उनके महान परिजनों के बलिदान के प्रति मैं अपना विनम्र अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज का यह विशेष दिन मेरे लिए भावनाओं से भरा हुआ है। एक ओर, मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के साथ बिताए गए अनमोल पलों की स्मृतियाँ हैं, वहीं दूसरी ओर, इस महान सेवा से विदा लेने का क्षण। मैं इस विदाई समारोह के आयोजन और आप सभी की उपस्थिति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। विदाई परेड के पश्चात डीजीपी सुधीर सक्सेना पुलिस मुख्यालय पहुंचे जहां उन्होंने नवनि्युक्त डीजीपी कैलाश मकवाना को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बेटन सौंपा।

राज्य सरकार का 01 वर्ष - जनकल्याण पर्व के रूप में मनाया जाएगा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

- 11 से 26 दिसंबर तक चलेगा विशेष अभियान
- महिला, किसान, युवाओं और गरीब कल्याण से जुड़े होंगे कार्यक्रम

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि राज्य शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश में 11 से 26 दिसंबर तक 'जन कल्याण पर्व' मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत सभी जिलों में महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण सहित विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि कार्यक्रमों के आयोजन के लिए मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। किसानों के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंसाना को, युवाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय को, गरीब कल्याण से जुड़ी समिति का अध्यक्ष पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल को और महिलाओं से जुड़ी समिति का अध्यक्ष महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया को बनाया गया है। संबंधित मंत्रीगण पूरे प्रदेश में कार्यक्रम के आयोजित के संबंध में विस्तृत रूपरेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 11 दिसंबर को भोपाल एवं सभी जिलों में गीता जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार ग्वालियर में 15 से 19 दिसंबर तक तानसेन समारोह आयोजित होगा।

किराए पर मकान लेने पर 18% जीएसटी, टैक्स चोरी पर लगेगी रोक नई व्यवस्था से किराए के व्यापार में आएगी पारदर्शिता

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश देशभर में किराए पर मकान लेना और देना अब एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। पहले, मकान मालिकों को अपनी किराए की आय पर जीएसटी चुकाना होता था, लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत किराएदारों को भी जीएसटी चुकाना पड़ेगा। इस नए नियम को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा गया है, जिसमें किराएदार को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य हो गया है। इसका उद्देश्य किराए के कारोबार में पारदर्शिता लाना और टैक्स चोरी को रोकना है। नई व्यवस्था के तहत, किराएदार को अब अपने किराए पर 18% जीएसटी चुकाना होगा। हालांकि, इसमें राहत की बात यह है कि किराएदार को जो भी टैक्स देना होगा, वह इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस मिल सकता है। इसका मतलब है कि किराएदार को सरकार से अपने द्वारा चुकाए गए जीएसटी का बड़ा हिस्सा रिफंड के रूप में वापस मिलेगा। इस नए नियम को लागू करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किराए की आय और भुगतान सरकारी रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज हो,

ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। पहले, किराए पर मकान देने वाले मकान मालिक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और अपनी आय के बारे में सरकार को बताते थे। लेकिन अब रिवर्स चार्ज



मैकेनिज्म के तहत यदि किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वह मकान मालिक से किराया लेते समय जीएसटी का भुगतान करेगा और उसी के बदले सरकार को जीएसटी का भुगतान करेगा। इसके परिणामस्वरूप, यदि मकान मालिक रजिस्टर्ड नहीं है और किराएदार रजिस्टर्ड है, तो किराएदार ही

जीएसटी चुकाएगा। यह व्यवस्था टैक्स की पारदर्शिता और सही तरीके से संग्रहण को सुनिश्चित करती है। नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को नियंत्रित करना है। पहले, कई मकान मालिक

किराए की जानकारी सही तरीके से सरकार के रिकॉर्ड में नहीं देते थे, जिससे टैक्स चोरी की घटनाएं होती थीं। अब किराएदार को रजिस्टर्ड किया गया है, ताकि वह अपनी किराए की जानकारी सही तरीके से सरकार को दे सके और दोनों पक्षों के बीच ट्रांजेक्शन पारदर्शी हो। इसके अलावा, यदि मकान मालिक जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किराएदार पर यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार को टैक्स का भुगतान करे। इससे टैक्स चोरी की संभावना कम हो जाएगी। नई व्यवस्था के लागू होने से किराए के व्यापार में पारदर्शिता आएगी, जिससे न केवल टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा, बल्कि यह एक

सुनियोजित और सिस्टमेटिक तरीके से टैक्स के संग्रहण में भी मदद करेगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि इस प्रणाली के माध्यम से किराए का कारोबार और संबंधित लेन-देन अधिक सुसंगत और सही तरीके से सरकार के रिकॉर्ड्स में दर्ज हो, ताकि सभी प्रकार के व्यापार में न्यायपूर्ण टैक्स संग्रहण हो सके।

मिथाइल आइसोसाइनेट गैस ने ली थी हजारों लोगों की जान कई हजार बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हुए

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश



भोपाल शहर में 3 दिसम्बर सन् 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नाम की एक विदेशी कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 15000 से अधिक लोगों की जान गई। बहुत सारे लोग कई तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हुए। यूनियन कार्बाइड को इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार पाया गया, लेकिन कम्पनी ने इस त्रासदी के लिए खुद को जिम्मेदार मानने से साफ इंकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 15000 लोगों की मृत्यु हो गयी और लगभग 500000 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए। भोपाल गैस काण्ड में मिथाइल आइसोसाइनेट (रूहृष्ट) नाम की जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका की रसायन और कीटनाशक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 1984 में भोपाल स्थित संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस के रिसाव को अब तक की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। मरने वालों के अनुमान पर विभिन्न स्रोतों की अपनी-अपनी राय होने से इसमें भिन्नता मिलती है। सरकारी आंकड़ों की मानें तो भोपाल गैस त्रासदी में मरने वालों की संख्या 3,787 थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में यह संख्या 15,724 से ज्यादा बताई गई है। जबकि सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि मरने वालों की संख्या 33 हजार से ज्यादा थी। मध्य प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने 3787 लोगों की गैस से मरने वालों के रूप में पुष्टि की थी। अन्य अनुमान बताते हैं कि 8000 लोगों की मौत तो दो सप्ताहों के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8000 लोग तो रिसी हुई गैस से फैली संबंधित बीमारियों से मारे गये थे। यह दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी थी। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव से करीब 558,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,478 थी। 3900 तो बुरी तरह प्रभावित हुए एवं पूरी तरह अपंगता के शिकार हो गये। भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता रहा है। इसीलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गये भोपाल-अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। कम्पनी के गैस पीड़ितों के साथ हुए एक समझौते और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के शुरुआत के साथ भारत में इसका अध्याय समाप्त हो गया।

शौचालय में रहकर पढ़ाई करने की वास्तविकता सामने लाने वाले कार्यवाही करने के बदले हालात बदलने की ज़रूरत - शिवसेना

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)

जगदलपुर। बीते बीते दिनों सोशल मीडिया पर नारायणपुर विधानसभा अंतर्गत सरकारी छात्रावास में शौचालय के अंदर रहकर पढ़ाई करने पर मजबूर विद्यार्थी की वास्तविक स्थिति दिखाई गई। सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोगों ने नारायणपुर विधानसभा में शासकीय छात्रावास की वास्तविक स्थिति को जान लिया है। यदि शासकीय छात्रावास पर



अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित हॉस्टल की अव्यवस्था को उज़ागर करने वाले के ऊपर कार्यवाही करने की धमकी दे रहे हैं

माननीय मंत्री महोदय जी

अरुण पाण्डेय
जिला अध्यक्ष, शिवसेना

सच्चाई को सामने लाते हैं। आज वर्तमान समय में सच्चे और निर्भय पत्रकार ऐसे भी बहुत ही कम गिनती के बचे हुए हैं। यदि जिम्मेदार ईमानदार और निर्भय लोगों को डराया धमकाया जायेगा तो बची खूँची पत्रकारिता भी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी।

शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन

पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम। 29- 30 नवंबर 2024 को दो दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता जिसका आयोजन शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम में किया गया जिस के

द्वारा कानून के विद्यार्थियों को एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया गया। विधि महाविद्यालय में कानूनी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिता का उद्घाटन दिनांक 29 नवंबर 2024 को डॉ रामकुमार चौकसे प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस नर्मदा पुरम के विशिष्ट आतिथ्य में एवं डॉक्टर कल्पना भारद्वाज प्राचार्य शासकीय विधि महाविद्यालय नर्मदापुरम की अध्यक्षता में किया गया। मूट कोर्ट प्रतियोगिता में महाविद्यालय की एलएलबी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की 6 टीमों ने हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल के रूप में लीगल एड एंड डिफेंस कार्डसिल के सदस्यों ने निष्पक्षता के साथ प्रतिभागियों के तर्क प्रस्तुति शैली और कानूनी ज्ञान का मूल्यांकन किया। प्रतियोगिता के प्रथम दिवस दो राउंड के माध्यम से प्रतिभागियों ने अपनी तर्क शक्ति का प्रदर्शन किया। द्वितीय दिवस फाइनल राउंड में दो टीमों ने सहभागिता की। समापन सत्र में श्रीमती शशि सिंह जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवम श्रीमती रुचि पांडे प्रथम वर्ग न्यायाधीश जुबनाइल कोर्ट एवं श्री सतीश तिवारी, पंकज तिवारी, आनंद तिवारी, श्रीमती पूजा अवस्थी, सुश्री पंखुड़ी बरडिया, श्री मंगल सिंह परिहार लीगल एड डिफेंस कार्डसिल के सदस्य उपस्थित रहे। प्रतियोगिता



का आयोजन महाविद्यालय के मूट कोर्ट ईचार्ज श्री राजदीप सिंह भदोरिया के मार्गदर्शन में किया गया। मूट कोर्ट प्रतियोगिता में विजेता रही टीम में तनुश्री तोमर, प्रार्थना गौर व संस्कार गुप्ता एवं उप विजेता रही टीम में नबीला कुरेशी, अनुराधा एवं वंशिता यादव को जिला जज एवं रुचि पांडे मैडम के द्वारा ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रतियोगिता में तनुश्री तोमर एलएलबी द्वितीय वर्ष बेस्ट स्पीकर

नबीला कुरेशी एलएलबी द्वितीय वर्ष द्वितीय बेस्ट स्पीकर एवं रेणुका एलएलबी प्रथम वर्ष तृतीय बेस्ट स्पीकर रही। बेस्ट मेमोरियल का पुरस्कार कविता राजपूत, भारती, वैशाली की टीम को प्रदत्त किया गया। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होने में महाविद्यालय के अधिकारियों डॉक्टर अभिषेक सिंह एवं श्री शिवाकांत मौर्य का भरपूर सहयोग रहा। महाविद्यालय के समस्त

विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक कार्यक्रम के सफल संयोजन हेतु सहभागिता की जिसमें जुगल किशोर एवं पीयूष शर्मा छात्र कन्वेनर व छात्र आयोजन समिति में अमन भट्ट, आनंद सिंह, पंकज आफजा, नूर, ईश्वर, राजकुमार, नरेंद्र ने कार्यक्रम के सफल संयोजन हेतु प्रयास किया। महाविद्यालय के श्री हरि प्रकाश मिश्रा, डॉ ओम शर्मा एवं मनोज शर्मा सहायक ग्रेड 3 उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एड्स जागरूकता रैली निकाली गई



पत्रकार बीआर अहिरवार नर्मदापुरम। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम में प्राचार्य डॉक्टर आर.के. चौकसे के संरक्षण में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत एड्स जागरूकता रैली निकालकर - चाहे जो मजबूरी

हो एड्स से सुरक्षा ज़रूरी है- नारे लगाकर जनजागरण किया कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वर्मा ने कहा कि वर्तमान में युवाओं में एड्स के प्रति जागरूकता लाना अनिवार्य है, मानव जीवन की सुरक्षा करना वर्तमान की प्राथमिकता होनी चाहिए जब युवा स्वस्थ होंगे तब भारत

स्वस्थ होगा। डॉक्टर सुनील कुमार दिवाकर ने कहा कि एड्स से बचाव के लिए एड्स जागरूकता का प्रचार प्रसार समुचित रूप से किया जाना चाहिए। छात्र धर्मेन्द्र कटारे ने एड्स पखवाड़े में किए जाने वाले कार्यक्रम- नुकड़ नाटक, रंगोली प्रतियोगिता, संगोष्ठी आदि की

जानकारी विद्यार्थियों को दी। युवा छात्र मनीष कीर, धर्मेन्द्र कटारे, पाखी माहुरकर, वैष्णवी मांझी, निकिता, किरण परिहार, रजनी, सुरभि साहू, अभिषेक कीर, आशीष कीर आदि विद्यार्थियों ने एड्स से सुरक्षा के विभिन्न उपायों पर चर्चा की।

उदयपुरा में हिंदू संगठनों की बड़ी रैली, तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन

संवाददाता हल्केवीर की न्यूज़

उदयपुरा- बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में शहर में हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। यह रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील परिसर पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हो रहे इन घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के मंदिरों और घरों पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और हत्याओं जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से इस विषय में हस्तक्षेप करने की अपील की। रैली में शामिल हजारों लोगों ने -जय श्री राम और हिंदू एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल



रहने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल भी तैनात रहे। अंत में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग

की गई कि भारत सरकार इस विषय पर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके।



राज्यपाल श्री पटेल उमंग गौरवदीप वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित अस्थिबाधित महिला एवं पुरुष व्हील चेयर डे एण्ड नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग, सामाजिक न्याय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय श्रीमती सोनाली वायंगणकर पोक्षे, आयुक्त श्री रामाराव भोसले एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। प्रतियोगिता का आयोजन ओल्ड कैप्टियन ग्राउंड में किया गया था। खेलते रहने वाला ही होता है विजेता

राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जीवन की सच्चाई है कि निरंतर प्रयास से ही परिणाम मिलते हैं। हारना-जीतना उतना मायने नहीं रखता है जितना निरंतर खेलते रहना। निरंतर खेलते रहने वाले ही विजेता होते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को उनके उत्साह और

मस्जिद में दूंट रहे भगवान , नया भारत खोदो अभियान



07 दिसंबर 2024, भावना मंगलमुखी, मुंबई

मैंने बचपन में एक ठेकेदार का चुटकुला सुना था -- ÷ यहां भी खुदा, वहां भी खुदा और जहां नहीं खुदा, वहां कल खुदेगा।÷ लगता है धर्म के ठेकेदारों ने इस चुटकुले को ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है।

जब 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू किया तो उनकी पार्टी को समर्थन दे रही भाजपा ने न सिर्फ अपना समर्थन वापस लेकर वी. पी. सिंह की सरकार गिराई अपितु पिछड़ों को हिंदुत्व के छाते के नीचे लाने के लिए तत्कालीन बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी कमंडल की राजनीति के अगुआ बनकर अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए रथयात्रा लेकर निकल गए। विवाद बढ़ता देख अगले प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव ने कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों के सांप्रदायिक एजेंडे को भांपते हुए धार्मिक पूजा उपासना स्थल अधिनियम 1991 बनाया जो अयोध्या राम जन्म भूमि को छोड़कर भारत के शेष सभी धार्मिक स्थलों को उनकी 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति को सुनिश्चित व संरक्षित करने का प्रावधान करता है। तब माना गया कि राम मंदिर - बाबरी मस्जिद विवाद सुलझते ही सांप्रदायिक राजनीति का अंत हो जाएगा और देश सौहार्द और शांति की ओर बढ़ेगा लेकिन 2018 में राम अयोध्या का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आते ही कट्टर हिंदुत्ववादियों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने 2021 में काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्थान पर भी शिव मंदिर होने का दावा किया। मामला फिर अदालत में गया और पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से बस इतना कहते हुए एक खिड़की खोल दी कि 1991 का पूजा उपासना कानून किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को परिवर्तित करने पर प्रतिबंध लगाता है जबकि सिर्फ सर्वे मात्र से उस स्थल का धार्मिक चरित्र नहीं बदलता इसलिए उसके मूल स्वरूप को जानने हेतु सर्वे की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि ऐसा आदेश उनके लिखित फैसले में बिल्कुल नहीं था लेकिन कुछ बहुसंख्यक सांप्रदायिक अधिकवक्ता सिर्फ चंद्रचूड़ जी के उक्त कथन को आधार बनाकर अलग - अलग मस्जिदों के सर्वे को लेकर

अदालत का दरवाजा खटखटाने लगे। शुरू में नारा लगा -- ÷ अयोध्या तो झांकी है, काशी - मथुरा बाकी है।÷ हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि अयोध्या, काशी, मथुरा ये हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं लेकिन अब आगे हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। अब मुझे याद आता है कि एक बार नेहरू जी ने कहा था कि -- ÷संघी अगर कहे कि कोई तुम्हारी भैंस को चुराकर पूरब की ओर गया है तो आपको अपनी भैंस की तलाश पूरब दिशा को छोड़कर अन्य सभी दिशाओं में करनी चाहिए। दो दिन पूर्व ही हर हिंदू को तीन बच्चे पैदा करने की सलाह वाले मोहन भागवत के बयान से भी उनका दोहरा चरित्र स्पष्ट होता है क्योंकि अधिकांश भक्त लगातार पिछले पांच साल से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहे थे और मैं भी इस मांग के समर्थन में रही हूं।

लेकिन चूँकि देश में महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, आत्महत्याएं निरंतर बढ़ रहे हैं और दस साल सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी के पास विकास के नाम पर कोई विशेष उपलब्धि नहीं है उल्टे अर्थव्यवस्था दिनोंदिन गर्त में जा रही है। साथ ही चुनावी घोटालों से ध्यान भटकाने के लिए भी ये तरह - तरह के प्रपंच करती रहती है। मेरा दावा है कि भाजपा बिना हिंदू - मुस्लिम किए चुनाव जीत ही नहीं सकती। मोदीजी ने 2002 में गोधरा दंगे करवाकर पहली बार गुजरात में प्रचंड बहुमत पाया था। 2013 में मुजफ्फर नगर दंगों की आग पर अपनी रोटी सेककर दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुए थे। 2019 में पुलवामा करवाकर शहीदों के नाम पर सहानुभूति के वोट बटोरें थे, जिसकी आज दिन तक कोई जांच नहीं हुई। 2024 से पहले मणिपुर को जलवाया फिर भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया तो बहराइच, सम्भल, अजमेर, आगरा, दिल्ली, उज्जैन जगह - जगह आग लगाने पर तूले हुए हैं और अब जब हर अदालत में भी संघी मोहरे बैठा दिए गए हैं तो जजों को दूल्कित बनाकर आए दिन अलग - अलग मस्जिदों के सर्वे का आदेश लाकर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे स्वघोषित राष्ट्रवादी अदालत में ऐसे केस लड़ने वाले अधिवक्ता विष्णु गुप्ता को गरीब बताकर कई हिंदुओं से बेहिसाब चंदा भी वसूल रहे हैं।

किसी विद्वान ने कहा है - ÷ भूतकाल रद्दी पेपर के समान है, वर्तमान न्यूज पेपर के समान है और भविष्य प्रश्न पेपर के समान है।÷ इसलिए कब तक हम अतीत में ही उलझे रहेंगे और आखिर कब हम भविष्य की समस्याओं और चुनौतियों पर कार्य करेंगे ? चीन और अमेरिका चांद पर जमीन खरीदने की बात करते हैं और हम मस्जिदों की खुदाई में लगे हुए हैं। लगता है अयोध्या के राम मंदिर में भी अंधभक्तों को भगवान की अनुभूति नहीं हुई है इसलिए अब अलग - अलग मस्जिदों के नीचे भगवान को ढूंढ रहे हैं।

पहले अयोध्या, फिर काशी, मथुरा, अजमेर, सम्भल ... अब भी नहीं संभले तो पता नहीं क्या होगा कल ? दो दिन पूर्व ही मोदी कैबिनेट के नफरती चिंटू गिरिराज सिंह ने बयान दिया जिसमें वह ताजमहल, कुतुबमीनार से लेकर लाल किले तक सभी को बिल्कुल हटा देने की बात कर रहा है। और कुछ अंधभक्त तो मस्जिद खोदो अभियान को मनरेगा से भी बेहतर बताते हुए कह रहे हैं कि मनरेगा में तो सिर्फ मिट्टी इधर - उधर करवाई जाती है लेकिन मस्जिद की खुदाई करने वालों को रोजगार के साथ - साथ हिंदू गौरव और स्वाभिमान भी मिलेगा। कुल मिलाकर यह देश अब हिटलर के रास्ते पर चल पड़ा है। जब ये नारा लगाते हैं कि % बंटेंगे तो कटेंगे % तो अधिकांश सांप्रदायिक लोग अपने - अपने संप्रदाय के लोगों को एकजुट रहने की बात करते हैं लेकिन वे भूल जाते हैं कि अलग - अलग संप्रदायों में बंटने से भारत देश का बंटोधार हो जाएगा। मैं मानती हूं कि मुगल शासकों ने प्राचीन मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें और मकबरे बनाए थे और इसलिए आप उन्हें रक्कर भी कहते हो तो उनके बनाए मस्जिद और मकबरों को तोड़कर आप सहिष्णु कैसे बन सकते हो ? मुझे तो लगता है जो स्वयं बड़ी लकीर नहीं खींच सकता वह दूसरों की लकीर मिटाने की कोशिश करता है अर्थात् जो कुछ बना नहीं सकता है, वह दूसरों की बनाई इमारतों को भी ध्वस्त करता है। मैंने सुना है कि अपने डंकापति को आलोचना सुनना पसंद नहीं है और आजकल लोगों में एक शिकायत भी बढ़ी है कि मुगलों की बनाई इमारतें और अंग्रेजों के बनाए पुल आज भी मजबूत हैं लेकिन साहेब के बनाए हुए पुल - सड़कें एक ही बारिश में ध्वस्त हो जाते हैं इसलिए न पुराना कुछ बचेगा, न लोग नकारात्मक तुलना कर पाएंगे।

वैसे मुझे तो यह आज दिन तक समझ नहीं आया कि भगवान(सर्वशक्तिमान) के घर(मंदिर) को एक इंसान कैसे तोड़ सकता है और अगर भगवान वास्तव में सर्वशक्तिमान है और उन्हें किसी मस्जिद के नीचे दबा दिया गया तो वे सदियों तक वहीं दबे रहने के बजाय उस मस्जिद का छप्पर फाड़कर ज्वालामुखी की तरह अपने आप बाहर क्यों नहीं आए और आखिर सर्वशक्तिमान भगवान की लड़ाई किसी वकील को क्यों लड़नी पड़ रही है ? क्या वे अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ सकते और अगर वे स्वयं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो वे सर्वशक्तिमान कैसे और वे लोगों का भला कैसे कर सकते हैं ? यही बात किसी मस्जिद और उनके खुदा, चर्च और उनके गोंड पर भी लागू होती है क्योंकि अगर वास्तव में दुनिया में कोई भगवान, खुदा या गोंड होता तो लोगों को न्याय के लिए कोर्ट - कचहरी जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मुझे इसमें आस्था से ज्यादा सामुदायिक स्तर पर जमीनों पर कब्जे, वर्चस्व और एक - दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई नजर आती है।

फिर भी अगर यही सिलसिला चलता रहा तो चूँकि हिंदू मंदिरों का निर्माण तो गुप्तकाल से शुरू हुआ था, पहले तो भारत बौद्ध हुआ करता था। इसलिए मुझे तो आशंका है कि कहीं बौद्ध भी इस लड़ाई में कूद गए तो फिर नारा हो सकता है -- ÷हिंदू - मुसलमान के बीच बौद्धों का प्रवेश, अब खुदेगा पूरा देश।÷ क्योंकि कहा जा रहा है कि इन एजेंडाधारियों के पास लगभग 1800 मस्जिदों और मजारों की सूची है और हो सकता है कल कोई मस्जिदों के अलावा राष्ट्रपति या संसद भवन के नीचे भी अपने भगवान के दबे होने का दावा कर दे। साथ ही मेरा दावा है कि अधिकांश मंदिरों के नीचे भी बुद्ध विहार और मठ मिलेंगे और शायद उनसे भी काफी नीचे हमारे देश की आज की अर्थव्यवस्था मिलेगी। अर्थव्यवस्था की इस दुर्दशा से ध्यान हटाने के लिए ही सभी लोगों को ऐसे विवादों में उलझाया जा रहा है लेकिन आखिर ये बदले की राजनीति सिर्फ खुदाई तक नहीं रुकेगी। अगर हम बाबर और औरंगजेब का बदला आज के मुसलमानों से लेंगे तो फिर दलित भी कहेंगे कि सामंतवादियों और मनुवादियों ने हमारे पूर्वजों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न किया था इसलिए हम भी उनकी आज की पीढ़ी से बदला लेंगे तो फिर ये धर्म के ठेकेदार किस बिल में घुसेंगे ? इन्हें पता होना चाहिए कि नेता लोग तो सांप्रदायिक आग लगाकर अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं लेकिन इसके शिकार होते हैं दंगों में शामिल होने वाले सिर्फ गरीब बेरोजगार युवा। साथ ही इनका दुष्प्रभाव उन दुकानों और बाजारों पर पड़ता है, चाहे वे दुकानदार हिंदू हो या मुस्लिम लेकिन जिनकी दुकान दूसरे सम्प्रदाय के नफरती लोगों की बस्ती या प्रभाव क्षेत्र में होती है। इतना ही नहीं इनकी ऐसी तुच्छ हरकतें ही पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए भी परेशानी पैदा करती है इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट अविलंब स्वतंत्र संज्ञान लेकर यथाशीघ्र एक सख्त कानून बनाए ताकि आज के बाद कोई भी धार्मिक संगठन चाहे वह हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई किसी भी धर्म से क्यों न हो, किसी अन्य धर्म के धर्म स्थल या संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई दावा न कर सके।

अंत में मैं देश के समस्त नागरिकों से भी अपील करती हूं कि मंदिर - मस्जिद का झगड़ा छोड़ो, इंसानियत से नाता जोड़ो। मंदिर - मस्जिद के बजाय अच्छे स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार, व्यापार, सड़क, बिजली, पानी, प्रदूषण इत्यादि समस्याओं पर मंथन करते हुए प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और गुणवत्तापूर्ण व गरिमामय जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत, कार्यरत व अग्रसर होते रहें।

विशेष ~ मैं पूर्णतया तार्किक हूं किसी की व्यक्तिगत आस्था से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं सदैव भारत की एकता व अखंडता के लिए आपसी सौहार्द और शांति की पक्षधार हूं।

रातापानी 'टाइगर रिजर्व' बनने से पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रातापानी बाघ अभयारण्य को प्रदेश का आठवाँ 'टाइगर रिजर्व' घोषित होने पर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व बनने से प्रदेश में पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के आठवें टाइगर रिजर्व के रूप में रातापानी बाघ अभयारण्य की अधिसूचना 2 दिसम्बर को जारी की गयी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह किसी भी राज्य की राजधानी से सटा पहला टाइगर रिजर्व है। राजधानी के पास स्थित होने से यहाँ न सिर्फ पर्यटन से रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे, बल्कि जंगल, बाघों तथा अन्य जंगली पशुओं का प्रभावी संरक्षण भी हो सकेगा। उन्होंने कहा कि गाँव के लोगों को परेशानी न हो, इसके लिये रातापानी अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले गाँवों को कोर क्षेत्र की जगह बफर क्षेत्र में रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कहा कि टाइगर रिजर्व बनने से रातापानी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी तथा भोपाल की पहचान टाइगर राजधानी के रूप में होगी। उन्होंने कहा कि रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का रकबा 763.812 वर्ग किलोमीटर तथा बफर एरिया का रकबा 507.653 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार टाइगर रिजर्व का कुल रकबा 1271.465 वर्ग किलोमीटर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क के लिये एनटीसीए से अनुमति मिल गयी है। इसके नोटिफिकेशन जारी करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गयी है, जो लगभग एक माह में पूरी हो जायेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश 'चीता स्टेट' भी बन चुका है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएँ दी हैं।

डंपर की टक्कर से युवक घायल

ज्ञान चन्द शर्मा/बालाघाट। लालबारी थाना पुलिस ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के मामले में अपराध पंजीबद्ध किया है पुलिस ने बताया है कि योगेश हरिनखेडे 34वर्ष साहूटोला मांझापुर निवासी ने थाने मे शिकायत दर्ज कराई है जिसमे उसने बताया है कि डंपर क्रमांक एमपी 22 जेईसी5053 के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारी है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है पीडित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शराब डंपर चालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले मे विवेचना मे लिया है।

अपने नाम के अनुरूप काम करती है संबल योजना - मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने संबल योजना में 225 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खातों में की अंतरित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संबल योजना आपात स्थिति में श्रमिकों के लिये अपने नाम के अनुरूप संबल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि मुश्किल और दुख की घड़ी में सरकार श्रमिकों के साथ है। उन्होंने कहा कि पीडित हितग्राही के परिजनों के लिए यह राशि राज्य शासन की ओर से संवेदनाओं के रूप में है। कठिनाई के समय में यह राशि श्रमिकों को अवश्य ही सहारा देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मंत्रालय से मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना (संबल) के अंतर्गत 10 हजार 236 हितग्राही श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ से



अब तक 6 लाख 16 हजार से अधिक प्रकरणों में 5,626 करोड़ से अधिक के हितलाभ दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल की सराहना करते हुए

कहा कि श्री पटेल ने संवेदनशीलता के साथ काम किया है। उन्होंने यह प्रयास किया है कि समाज के अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि संबल योजना में एक करोड़ 73 लाख से अधिक श्रमिक भाई-बहन अपना पंजीयन करा चुके हैं। इनमें से संबल 2.0 योजना में 32 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठी योजना है, जिसमें करोड़ों जरूरतमंद परिवार को बच्चे के जन्म से लेकर पूरे जीवनकाल तक मदद की जाती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि घर-घर जाकर सामान और सेवाएं देने वाले श्रमिकों को असंगठित श्रमिकों की श्रेणी में रखा गया है और इन्हें भी मार्च 2024 से संबल योजना का लाभ दिया जा रहा है।



है और किस प्रकार प्रभु नाराज होकर दंड देते हैं या प्रसन्न होकर पुरस्कार देते हैं यह इस कथा का केंद्र बिंदू है। सत्यनारायण भगवान की पूजा में खासकर केले के पत्ते, नारियल, पंचफल, पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, तुलसी की आवश्यकता होती। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान और पंजरी अर्पित की जाती है। विधिवत रूप से व्रत रखने और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। इस कथा का तिरस्कार करने या मजाक उड़ाने से व्यक्ति के जीवन में संकटों की शुरुआत हो जाती है।

नाडा के बैन पर भड़के बजरंग पुनिया, बोले- अगर मैं आज बीजेपी में चला जाऊं तो सभी प्रतिबंध हट जाएंगे

नईदिल्ली, एजेंसी। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता और अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पहलवान बजरंग ने उन पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) की ओर से लगाए गए चार साल के प्रतिबंध पर भाजपा सरकार और बृजभूषण शरण पर हमला बोला है। बजरंग पुनिया ने कहा कि ये साजिश किसानों और महिला पहलवानों का साथ देने के लिए रची जा रही है। बजरंग पुनिया ने सरकार और नाडा को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और नाडा मुझ पर कितने भी प्रतिबंध लगा ले, हम पहले भी नहीं झुके थे और अब भी नहीं

झुकेंगे। मुझ पर बीजेपी में शामिल होने का भी दबाव बनाया गया था आज अगर मैं बीजेपी में चला जाऊं तो सभी प्रतिबंध मुझसे हट जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस वर्ग के खिलाफ अत्याचार होगा उस वर्ग के साथ बजरंग हमेशा खड़ा रहेगा।

डोप एजेंसियां बृजभूषण शरण के हाथ में : बजरंग पुनिया ने कहा कि उनका पहला ऐसा केस है जिसमें चार साल का प्रतिबंध लगाया गया। ऐसे आरोप में दो साल के ही प्रतिबंध का प्रावधान है। डोपिंग एजेंसी को उनकी तरफ से की गई शिकायत पर सालभर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना सब कुछ खुद ही



बयां करता है। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण को बचाने में सरकार जुटी है। बृजभूषण शरण ने एक-दो महिला पहलवानों को डोप में फंसाने का काम किया। बृजभूषण शरण के हाथ में डोप एजेंसियां हैं।

अपने हक के लिए आखिर तक लड़ता रहूंगा : बजरंग पुनिया ने कहा कि यह निर्णय राजनीति से प्रेरित है। इसके खिलाफ एक बार फिर वे अदालत का सहारा लेंगे। बजरंग पुनिया ने कहा कि उन्होंने एक साल पहले शिकायत दी थी कि डोपिंग एजेंसी की टीम उनके पास एक्सपायरी डेट की किट लेकर पहुंचे थे। इसके लिए उन्होंने सबूत भी दिए

थे, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होना सरकार व एजेंसी की नीयत पर सवाल उठाता है। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैंने कभी डोप टेस्ट देने से मना नहीं किया। नाडा की टीम एक्सपायर किट से मेरा टेस्ट लेना चाहती थी, जिसका मैंने विरोध किया था। फेडरेशन और सरकार ने मेरे करियर को खत्म करने की चाल चली है। प्रतिबंध का मकसद यह है कि मैं अन्याय चुपचाप सहता रहूं। चाहे मुझे ज़िंदगी भर के लिए निलंबित कर दिया जाए, लेकिन अन्याय के विरुद्ध आवाज बंद नहीं होगी। मैं इस फैसले के विरुद्ध अपील करूंगा और अपने हक के लिए

आखिर तक लड़ता रहूंगा। किसान नेता डल्लेवाल की गिरफ्तारी के विरोध में खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे बजरंग किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस हिरासत में लेने का विरोध करते हुए बजरंग पुनिया एक दिन पहले खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे। बजरंग पुनिया ने कहा कि किसान नेता डल्लेवाल को बिना वजह हिरासत में लेना निंदनीय है। यह बर्दाश्त के बाहर है। बजरंग पुनिया ने कहा था कि आज संविधान दिवस है और पंजाब पुलिस और सरकार जो कर रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या है। मैं एक किसान परिवार से हूँ इसलिए मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहूंगा।

खड़गे के बयान पर भाजपा का पलटवार, संबित पात्रा बोले- ईवीएम हटाओ या न हटाओ, जनता ने कांग्रेस को साइड कर दिया

नईदिल्ली, एजेंसी। भारतीय जनता पार्टी सांसद संबित पात्रा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाने को लेकर बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस था। संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस कार्यालय में ईवीएम को कोसा है और कहा कि हमें ईवीएम हटाना है और बैलेट पेपर को फिर से लेकर आना है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए पात्रा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप ईवीएम हटाओ या न हटाओ, लेकिन जनता ने कांग्रेस को साइड में रख दिया है। करीब हर राज्य के चुनाव में कांग्रेस साइड लाइन कर दी गई है। महाराष्ट्र में तो नेस्तनाबूद हो गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई है तो वहीं कांग्रेस का सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि हर राज्य के चुनाव में कांग्रेस को किनारे कर दिया गया है, यहां तक कि झारखंड में भी। आज कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का सफाया हो गया है। महाराष्ट्र में उन्हें महज 16 सीटें मिली हैं। महायुति ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस का महाराष्ट्र से सफाया हो गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य लोगों सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरे पर निराशा स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी



जैसे एक वरिष्ठ नेता ने कल एक वाक्य कहा कि एससी-एसटी-ओबीसी और गरीबों का वोट ईवीएम के कारण खराब हो रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या सोचते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के लोग कि एससी-एसटी-ओबीसी समाज इतना अनपढ़ है कि उन्हें ईवीएम में वोट करना नहीं आता? कांग्रेस की ऐसी सोच एससी-एसटी-ओबीसी समाज का अपमान है। मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि कमजोर तबकों का वोट जाया हो रहा है और ऐसे में मतपत्रों के जरिए मतदान होना चाहिए तथा इस मांग को लेकर 'भारत जोड़ो यात्रा' की तरह एक मुहिम शुरू करनी है। उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों की ओर से आयोजित 'संविधान रक्षक अभियान' कार्यक्रम में यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जाति जनगणना कराने से डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि ऐसा करने से सभी वर्ग अपनी हिस्सेदारी मांगने लगेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब तबके के लोग अपनी पूरी

शिवसेना यूबीटी भी टूटेगी! उद्धव ठाकरे चाहें बनी रहे एमवीए, पर हार के बाद विधायक उखड़े

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी में टूट के आसार हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के अधिकांश विधायक एमवीए से अलग होने का दबाव बना रहे हैं। साथ ही चुनावों में अपने दम पर उतरने का सुझाव दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी ने 96 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 20 पर जीत हासिल की थी। साल 2019 में 105 विधानसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बनी थी। तब उसने अविभाजित शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि, खबरें आई कि मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बनी और उद्धव ने अलग होने का फैसला कर लिया था। तब शिवसेना ने अविभाजित एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार का गठन किया था और खुद मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, जून-जुलाई 2022 में एकनाथ शिंदे समेत अधिकांश विधायकों ने शिवसेना से अलग होने का फैसला कर लिया था, जिसके बाद एमवीए सरकार ने बहुमत का आंकड़ा गंवा दिया और राज्य सरकार गिर गई। इसके बाद शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को ठाकरे की तरफ से बुलाई गई बैठक में अधिकांश विधायकों ने कथित तौर पर गठबंधन छोड़ने की अपील की है। अखबार को सूत्रों ने बताया है कि आदित्य ठाकरे, संजय राउत और ठाकरे के अलावा पार्टी के कई और बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष रखने के लिए गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में हैं। अखबार से बातचीत में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने कहा, हमारे कई विधायकों को लगता है कि अब समय आ गया है कि शिवसेना यूबीटी स्वतंत्र राह बनाए, खुद के दम पर चुनाव लड़े और किसी गठबंधन पर निर्भर न रहे। शिवसेना कभी भी सत्ता के पीछे नहीं थी...। जब हम हमारी विचारधारा पर अडिग रहेंगे, तो यह अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा। माना जाता है कि 2022 में टूट के बाद जब कई बड़े नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए थे, तब कैडर ठाकरे परिवार का वफादार बना रहा था। अखबार के अनुसार, शिवसेना यूबीटी के कई नेता एमवीए में एकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। वह सीट शेयरिंग में देरी, कांग्रेस नेताओं की तरफ से शिवसेना यूबीटी उम्मीदवारों के समर्थन के बजाए निर्दलीयों की मदद का भी हवाला दे रहे हैं।

शक्ति लगाकर वोट दे रहे हैं, उनका वोट फिजूल जा रहा है...हमें मतपत्र के जरिये वोट चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी के घर, या अमित शाह के घर में मशीन रखने दो, अहमदाबाद के किसी गोदाम में रखने दो। लेकिन हमें मत पत्र

चाहिए। खरगे ने कहा कि पार्टी की तरफ से एक मुहिम शुरू करनी चाहिए। सभी पार्टियों को कहेंगे। जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में 'भारत जोड़ो यात्रा' निकाली गई थी, वैसे ही 'मत पत्र चाहिए' की मुहिम शुरू करनी होगी।

टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी से पूछा- गौतम अडानी से मुलाकात के दौरान क्या हुई थी बात?

नईदिल्ली, एजेंसी। उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा हो रहा है। इसका असर आंध्र प्रदेश तक में देखने



को मिल रहा है, जहां तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) और भाजपा गठबंधन की सरकार है। टीडीपी के प्रवक्ता अनम वेंकटरामण रेड्डी ने बुधवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से उद्योगपति गौतम अडानी के साथ उनकी मुलाकातों का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है। टीडीपी नेता ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआरसीपी सरकार ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अडानी ग्रुप से बिजली खरीदने के लिए गोपनीय रूप से फाइलों पर हस्ताक्षर किए। उनका दावा है कि कई विभागों के विरोध के बावजूद ऐसा किया गया। उन्होंने अमेरिका की एक अदालत में अडानी के खिलाफ लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों के संदर्भ में जगन मोहन रेड्डी से सफाई मांगी है।

1750 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोप : टीडीपी सूत्रों के अनुसार, अमेरिका की अदालत में दाखिल किए गए दस्तावेजों में अडानी ग्रुप पर 1,750 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। टीडीपी नेताओं का कहना है कि इस मामले की जांच केंद्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए और वाईएसआरसीपी सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए गए पावर खरीद समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का बयान : आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, मेरे पास अमेरिका की अदालत में दाखिल आरोपों की पूरी रिपोर्ट है। हम इसे गहराई से अध्ययन करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। हम जनता को बताएंगे कि हम क्या कदम उठाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान हुए इन आरोपों ने आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी अदालत के आरोप पत्र में कहा गया है कि अडानी ने फॉरेन ऑफिशियल 1 नामक एक उच्च सरकारी अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की।

बांग्लादेश के हाल पर भारत में भड़के सीएम मणिक साहा - सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले खुद मिट गए

अगरतला, एजेंसी। बांग्लादेश में हिन्दू भिक्षु चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी की मुद्दा तूल पकड़ रहा है। अब भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा ने कहा है कि सनातन धर्म को जिसने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो खत्म हो गए हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से ही बांग्लादेश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। उन्हें सोमवार को ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। सीएम साहा ने कहा, सनातन धर्म न्याय और मूल्यों से जुड़ा है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वह खुद ही खत्म हो गए हैं। इधर, पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में सनातनी अल्पसंख्यकों, धार्मिक संस्थानों और सनातनी भावनाओं पर जारी हमले पूरी तरह अलोकतांत्रिक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं मानवाधिकारों के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं। देव ने कहा, मैं ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूँ...। बांग्लादेश के चटगांव शहर में एक वकील की हत्या के मामले में बुधवार को कम से कम छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिन्दू भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी के अनुयायियों और पुलिस के बीच झड़प के दौरान एक वकील की हत्या के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है।

कांग्रेस पर बढ़ा मुसलमानों को आरक्षण देने का दबाव, 4 फीसदी कोटा के लिए हलचल तेज

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में मुसलमानों को 4 फीसदी आरक्षण का मुद्दा फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। खबर है कि हाल ही में हुए उपचुनावों में जीत के बाद कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम कोटा बहाल करने का दबाव बढ़ने लगा है। फिलहाल, इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कोटा खत्म कर दिया था, लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि कर्नाटक में कोटा बहाल कब तक किया जाएगा। खास बात है कि साल 2023 में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम कोटा का मुद्दा कांग्रेस के लिए काफी अहम साबित हुआ था। मुख्यमंत्री



सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अगुवाई में सरकार गठन में इसने बड़ी भूमिका निभाई थी। अब कांग्रेस को उपचुनाव में भी बड़ी सफलता हाथ लगी है।

एक अखबार के अनुसार, शिवाजीनगर से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद का कहना है कि

कोटा बहाल होगा और वह इसे समुदाय का हक बताते हैं। उन्होंने कहा, हमें भी समाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने जांच के बाद इसे तर्कसंगत बनाया था। रातों रात इसे छीना नहीं जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि

राज्य सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है।

अखबार ने पार्टी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि 4 फीसदी कोटा को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है, लेकिन सरकार सही समय का इंतजार कर रही है। कहा जा रहा है कि

लोकसभा और उपचुनावों के चलते ऐलान नहीं हो सका, क्योंकि सरकार को डर था कि इससे लिंगायत और वोडकालिगा वोट प्रभावित होंगे। खास बात है कि भाजपा सरकार में दोनों समुदायों को 2 फीसदी अतिरिक्त कोटा का लाभ मिला था। साल 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने मुसलमानों के लिए अलग से 4 प्रतिशत आरक्षण की बात कही थी। वहीं, बौद्ध और अनुसूचित जाति में धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों को रिजर्वेशन मेट्रिक्स के वर्ग 1 और 2ए में शामिल करने का फैसला किया था। 27 मार्च 2023 तक यह व्यवस्था जारी रही। इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया।